(घ) मध्य प्रदेश में कुल कितने उद्योग कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं;

(ङ) आगामी वर्षों में कोयले की पूर्ति में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत कमी होने का अनुमान है ; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) (क) और (ख) कोल इंडिया लि० ने दिनांक 1-10-91 से कोयले की बिक्री की अग्रिम अदायगी की प्रणाली शुरु की है । यह प्रणाली केवल विद्युत क्षेत्र के लिए लागू की गई है । अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के संबंध में कोल इंडिया लि० विद्यमान प्रणाली ही जारी रखे हुए है।

(ग) कोल इंडिया लि० ने यह सूचित किया है कि रेलवे लदान की तारीख से 24 से 28 घंटे की अवधि के बीच अग्रिम रूप में प्रतिदिन के आधार पर कोयला के वैगनों का आवंटन करता है। आमतौर पर आवंटित वैगनों में आवंटन किए जाने की तारीख से 1 दिन से 7 दिन के बीच की अवधि में लदान किया जाता है ।

(घ) देश के गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति में कुछ कमी रही है जिसमें मध्य प्रदेश के उपभोक्ता भी शामिल हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे विद्युत, इस्पात, लोको, सीमेंट और उर्वरकों आदि को रेल द्वारा कोयले के संचलन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण हुआ है । किंतु वर्ष 1991-92 के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं का कोयले की आपूर्ति लगभग उतनी ही मात्रा में की गई जितनी कि वर्ष 1990-91 के दौरान की गई थी । सरकार ने सभी कोयला कंपनियों को इस आशय के निर्देशन दे दिए है कि वह सभी गैर-महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को रेल अथवा सड़क द्वारा संयोजित मात्रा की न्यूनतम 50% आपूर्ति करें । कोल इंडिया लि० को यह भी सलाह दी गई है कि व सभी उपभोक्ताओं को पिटहैड स्टाक से अप्रतिबंधित आधार पर 20 मि० टन कोयला प्रदान करें । कोयला उपभोक्ता उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत विनिर्दिष्ट की गई खानों से बिना किसी प्रायोजन के एक बार में 1000 टन तक कोयले को उठाये जाने की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं ।

(ङ) और (च) यह संभावना है कि देश में सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयले की उपलब्धता में आगामी वर्षों में वृद्धि हो जाएगी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिदृश्य के अनुसार योजना अवधि के दौरान कोयले की उपलब्धता और मांग के बीच काफी कमी होने की कोई संभावना नहीं है ।

कोल इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता

3122. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान बजटीय सहायता के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड को कितनी धनराशि दी है ;

(ख) क्या वित्तीय विवशताओं को देखते हुए सरकार कोल इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता बंद करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) कौन-कौन सी कंपनियों (कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन) लगातार घाटे में चल रही है और उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) कौन-कौन सी कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(च) अर्जित लाभ से पिछड़े हुए क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड क्या प्रयास कर रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) :(क) सरकार ने पिछले वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० को बजटीय समर्थन के रूप में निम्नलिखित राशि का आवंटन किया :—

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1990-91 . .	600
1991-92 . .	399

(ख) और (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० घाटे में चल रही है। उन्हें लाभकारी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) मशीनरी के बेहतर उपयोग और और श्रमशक्ति पर रोक लगाकर तथा साथ ही साथ तैनातों पर सख्त नियंत्रण रखकर उत्पादकता में वृद्धि;

(2) बिजली की निरन्तर आपूर्ति में वृद्धि में वृद्धि किए जाने के लिए गृहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना।

(ङ) लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के नामों के साथ साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रु० में)

(लाभ(+)हानि(-) कोयला मूल्य धारित खाता से पूर्व)

कंपनी का नाम	1989-90	1990-91
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०, (से.को.लि.)	(+) 11.51	(+) 21.00
नार्दन कोलफील्ड्स लि० (ना.को.लि.)	(+) 277.66	(+) 292.75
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (वे. को.लि.)	(+) 20.54	(—) 119.71
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सा.ई.को.लि.)	(+) 294.80	(+) 167.91

वर्ष 1991-92 के लिए खातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(करोड़ रु० में)

	(लाभ(+) हानि(-)कोयला मूल्य धारित खाते के बाद)	
से०को०लि०	(+) 10.76	(+) 5.26
ना०को०लि०	(+) 2.10	(+) 22.58
वे०को०लि०	(—) 30.94	(—) 95.40
सा०ई०को०लि०	(—) 32.32	(—) 20.79

(च) सामान्यतः कोयला खानें पिछड़े इलाकों में स्थित है। कोयला खानों का आधारभूत ढांचा संबंधी विकास आसपास के क्षत्रों के विकास में योगदान देता है। कोयला कंपनियां सामुदायिक विकास पर खर्च करती है।

Exploitation of Jayamkonda Lignite reserves

3123. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of COAL be pleased to state the proposals with Government to exploit Jayamkonda Cholapuram resources in view of the estimate of 1150 million tonnes Lignite reserves in Jayamkonda Cholapuram in Tamil Nadu which is nearly 17.8 per cent of the total estimated reserves of India?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL SHRI S. B. NYAMAGOUDA): Government of India in the Ministry of Coal/NLC Ltd. do not plan to exploit lignite deposits in Jayamkonda Cholapuram area in Trichy district, Tamilnadu at present.

However, State Govt. of Tamilnadu, in Oct. 1991 requested Ministry of Coal to accord approval to undertake mining of